Ex.P-273

कथन – विजय अग्रवाल

S-(34)

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	विजय अग्रवाल पिता श्री रामचन्द्र अग्रवाल
उम्र	–	55 वर्ष
पता	–	निर्मल धर्मकांटा के पास, रायपुर रोड़, धमतरी (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	98274–62487
व्यवसाय	–	अभिषेक इंडस्ट्रीज राईस मिल के संचालक, धमतरी (छ0ग0)

---00---

मैं विजय अग्रवाल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं धमतरी में निर्मल धर्मकांटा के पास, रायपुर रोड़ धमतरी में अभिषेक इंडस्ट्रीज के नाम से राईस मिल है। इस राईस मिल को मैं वर्ष 2010 से किराये में लेकर संचालित कर रहा हूं। इस मिल के मालिक श्री सुधीर सिंघल निवासी धमतरी है। मिल में मुख्य तौर पर शासकीय कस्टम मिलिंग का कार्य किया जाता है। मार्कफेड से धान लेकर उसका चावल बनाकर नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में दिया जाता है। धमतरी चावल के मामले में सरप्लस जिला है। अतः यहां अन्य जिलों से चावल नहीं लाया जा सकता। अगर इस प्रकार चावल लाया जायेगा तो इससे नागरिक आपूर्ति निगम को नुकसान होगा। सरप्लस जिले में अगर चावल लाया गया तो ट्रासंर्पोटेसन, लोडिंग–अनलोडिंग का खर्चा अलग से नान को उठाना पड़ता। धमतरी से मुख्य तौर से बस्तर की ओर चावल जाता है क्योंकि वहा धान की उपज कम हैं एवं राईस मिल की संख्या भी कम है। पिछले वर्ष मेरे द्वारा 30–35 लॉट चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया गया था। 01 लॉट में 270 क्विंटल चावल होता है। इस वर्ष अभी तक 24–25 लॉट चावल जमा किया गया है। चावल जमा करने की अवधि 01 नवम्बर से 31 अक्टूबर तक होता है किन्तु इस वर्ष माह दिसम्बर से प्रारंभ हुआ है। नान में चावल जमा होने का पेपर प्रस्तुत करने पर ही मार्कफेड द्वारा अगला लॉट दिया जाता है। धमतरी में नान के गोदामों में चावल जमा करने के लिये जगह की समस्या हमेशा बनी रहती है। नागरिक आपूर्ति निगम धमतरी के अधिकारियों द्वारा स्पेश बनाने के लिये तथा क्वालिटी में समझौता एवं अन्य सुविधा के एवज में 08रू. प्रति क्विंटल की दर से वसूली की जाती है। यदि पैसा न दे तो हम लोगों के द्वारा दिये चावल में मानक क्वालिटी से ब्रोकन ज्यादा दिखा कर वापस कर दिया जाता है, वापस करने पर गोदाम से वापस मिल ले जाने में ट्रासर्पोटिंग खर्च एवं लेवर खर्च की नुकसानी होती है। इस नुकसान से बचने के लिये मजबूरी में नागरिक आपूर्ति निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक को पैसा देना पड़ता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 04.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ